

समक्ष माननीय राजस्व मंडल मोप्र० ग्वालियर

मुक्ता

/2018 निगरानी

क्रमांक 3970/2018/माननीय राजस्व मंडल मोप्र० ग्वालियर

1. जानकी वाई पत्नि स्व. भगतराम बजाज सिधी

2. विजय पिता स्व. भगतराम बजाज सिधी

3. रमि पिता स्व. भगतराम बजाज सिधी

4. सरिता पुत्री स्व. भगतराम बजाज सिधी

सभी निवासीगण संत कंवरराम वार्ड तहसील व जिला
सागर म.प्र।

आवेदकगण

श्री अदित्य शर्मा
काय नं. २४-६-१२-१९
प्रमुख न्यायिक बोर्ड हैन्स
टिक्का ६-७-१८ मियन।

काय अफ कोर्ट २४-६-१८
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

१. मनोहरलाल पिता चेतनदास सिधी निवासी संत
कंवरराम वार्ड तहसील व जिला सागर म.प्र.

२. भ.प्र.शासन

अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अतर्गत धारा 50 के तहत मोप्र० भू-राज्य
सहिता 1959 विरुद्ध आयुक्त सागर संभाग सागर के अपील प्रकरण के
432/ 2017-2018 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 16.4.2018 के
विरुद्ध।

माननीय महोदय,
सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :-

प्रकरण के ग्राम्यिक तथ्य :-

१. यहकि प्रकरण के संक्षिप्त में दिताण इस प्रकार है कि उक्त विवादित भूमि नजूल
व्लाक 23 मे से प्लाट क 26 कुल 1250 वर्गफुट स्थाई पटठे पर झामटमल को प्राप्त
हुई थी झामटमल के दो सन्तान दो साबूमल एवं श्रीमती भानीवाइ जिसने साबूमल की
मृत्यु दिनांक 1983 को हो चुकी है। एवं पुत्री श्री श्रीमतीभानी वाई की शादी होकर
अपनी ससुराल कटनी केम्प मे रहती है। झामटमल के वारिस साबूमल ने उक्त
प्लाट को आवेदकगण को रातिस्तर्ले विक्रय पर से आवेदकगण के पिता भगतराम
वार्ड टोपनदास सिधी को विक्रय कर दिया गया जो वर्तमान मे काविज है।

२. यहकि, अनावेदक मनोहरलाल ने आवेदकगण को लगै पक्षकार बनाये एक आवेदन
पत्र धारा 110 के तहत नजूल अधिकारी जिला सागर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमे
आवेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया गया जिस आवेदन पत्र ने उल्लेख किया है।



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3970/2018/सागर/भू.रा.

जानकीबाई विरुद्ध मनोहरलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-07-2018	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक श्रीमती जानकीबाई के अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन को पूर्व में दिनांक 06-07-2018 को सुना गया ।</p> <p>3. ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-04-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया ।</p> <p>4. आयुक्त के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन कर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है आवेदक द्वारा अपील लगभग 17 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई एवं उक्त विवादित आदेश की जानकारी उसे किस प्रकार हुई इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है । अतएव अवधि विधान की धारा 5 के अतंगत प्रस्तुत आवेदन पत्र तथ्यहीन होने से निरस्त किया जाता है ।</p> <p>5. आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है । जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p style="text-align: right;"><i>मामूल संख्या 16-7-19</i></p>